

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग **II--खण्ड** 3--उपलण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29]

नर्षे विल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 17, 1974/पीष 27, 1895

No. 29]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 17, 1974/PAUSA 27, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा का सकी।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate complication

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 17th January 1974

S.O. 42(E)/IDRA/74.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 36(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the industrial undertaking known as Messrs. Indian Rubber Manufacturers Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended upto 18th January, 1974 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto 18th January, 1974;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for another one year commencing from the 19th January, 1974;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 18th January, 1975.

[No. F.25/5/72-CUC] D. K. SAXENA, Jt. Secy.

घौद्योगिक विकास मंत्रासय

ग्रादेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1974

काठ ग्राठ 42(म)/ग्राई श्री ग्रार ए/74.—यतः केन्द्रीय सरकार ते, भारत सरकार के ग्रीशोगिक विकास मंद्रालय (ग्रीशोगिक विकास विभाग) के ग्रादेश संठकाठग्राठ 36 (ई)/18 एक वो/ग्राई श्री ग्रार ए/73, तारीख 19 जनवरी, 1973 (जिरो इसमें इसके पण्चात् उक्त ग्रादेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास ग्रीर विनियमन) ग्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि राजपक्ष में उक्त ग्रादेश के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदान्नों, सम्पत्त के हस्तान्तरण-पत्नों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, या ग्रन्य लिखतों या उनमें से किसी का प्रवर्तन जिसका मैसर्स इंडियन ,रवड़ मैनुफेक्चरसं लिमिटेड, कलकत्ता नामक ग्रीशोगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त ग्रीशोगिक उपक्रम को लागू हो, 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेगा ग्रार उक्त तारीख से पूर्व उसके ग्रधीन प्रोव्भूत या उद्भूत होने वाले सभी ग्रधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यताएं ग्रीर दायित्य 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेंगे ;

श्रीर यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त श्रादेश की श्रवधि एक वर्ष के लिए श्रीर बढ़ाई जानी चाहिए, जो 19 जनवरी, 1974 से प्रारम्भ होगी ;

ग्रत: ग्रब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास ग्रौर विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उप धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त ग्रादेश की श्रवधि 18 जनवरी, 1975 तक बढ़ाती है।

[सं ॰ फा ॰ 25/5/72-सी यू सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।